भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2183

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

तेलंगाना में सड़क संपर्क में सुधार

2183. श्री इटेला राजेंदर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने उत्तरवर्ती राज्य तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या इस प्रस्ताव में जिला मुख्यालयों, औद्योगिक गलियारों, पर्यटन और तीर्थ केन्द्रों, पड़ोसी राज्यों और आर्थिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाले 16 राज्यीय सड़क मार्गों का उन्नयन कर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना शामिल है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-765 के हैदराबाद-श्रीशैलम खंड पर चार लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड को छह लेन का बनाने के लिए भी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और तेलंगाना में इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्यीय सड़कों, जिनमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, को नए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में घोषित करने / उन्नयन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। एनएच की घोषणा, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात सघनता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के व्यापक सिद्धांतों के आधार पर समय-समय पर राज्य सड़कों को एनएच के रूप में अधिसूचित करने के निर्णय लिए जाते हैं। सरकार ने 2014 से तेलंगाना में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया है।

(ग) और (घ) एनएच-765 के हैदराबाद-श्रीशैलम खंड पर चार लेन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने परियोजना की लागत में अंशदान देने के साथ-साथ मालिकाना शुल्क की वसूली से छूट देने और परियोजना के एसजीएसटी घटक की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत दे दी है।

एनएच-65 के हैदराबाद से विजयवाड़ा खंड को 6 लेन का बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्शदाता को भी नियुक्त किया गया है। लगभग 230 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए संरेखण को मंजूरी दे दी गई है।

*****